उर्वरक संबंधी संसदीय स्थायी समिति के पांचवें प्रतिवेदन की एक प्रति (अंग्रेज़ी तथा हिन्दी में) सभा पटल पर रखता हूँ।

REPORT OF THE COMMITTEE ON EMPOWERMENT OF WOMEN

SHRIMATI VANDANA CHAVAN (Maharashtra): Sir, I lay on the Table, a copy (in English and Hindi) of the Second Report (Seventeenth Lok Sabha) of the Committee on Empowerment of Women (2019-2020) on Action taken on the Fifteenth Report of the Committee (Sixteenth Lok Sabha) on the subject 'Working Conditions of Women Teachers in Schools'.

MATTERS RAISED WITH PERMISSION

Need to meet the irrigation needs of Sirmor and Semaria regions from the Bargi and Bansagar Irrigation Projects

श्री राजमणि पटेल (मध्य प्रदेश): माननीय सभापति जी, मैं बरगी तथा बाणसागर नहर से सिरमौर तथा सेमरिया क्षेत्र में सिंचाई के संबंध में कहना चाहता हूँ। बाणसागर सिंचाई परियोजना से किसानों को सिंचाई की सुविधा उपलब्ध कराई जा रही है, लेकिन जिला त्योंथर, रीवा के लिए सिंचाई हेतु क्योटी नहर का निर्माण हेतु सिरमौर मुख्यालय से भूमिगत नाली का निर्माण कराए जाने से सिरमौर मुख्यालय तथा राजगढ़, दुरहरा, बलहारा, कररिया आदि गाँवों में किसान सिंचाई सुविधा से वंचित हो रहा है। मैं माननीय सिंचाई मंत्री जी से अनुरोध करना चाहता हूँ कि क्योटी नहर का निर्माण कार्य में ऊपरी सतह से नाली, नहर का निर्माण कराया जाए अथवा सिरमौर मुख्यालय के पास मुख्य नहर से लिफ्ट कराकर किसानों को सिंचाई हेतु पानी देने के आदेश देने की कृपा करें, ताकि सिरमौर मुख्यालय, राजगढ़, दुलहरा, बलहारा और कररिया आदि गाँवों के किसानों को सिंचाई की सुविधा मिल सके।

माननीय सभापति महोदय, इसी तरह से सेमरिया क्षेत्र पहाड़ी क्षेत्र है। वहाँ सिंचाई के साथ-साथ पीने के पानी की भी समस्या है, मवेशियों के लिए पानी की सुविधा उपलब्ध नही है। इस पहाड़ी अंचल के लिए बरगी बाँध सिंचाई नहर निर्मित कराकर जरमोहरा सिंचाई बांध सेमरिया में पानी पहुँचाकर सेमरिया पहाड़ी क्षेत्र में गाँवों के वंचित किसानों को सिंचाई की सुविधा उपलब्ध कराने हेतु तत्काल योजना की स्वीकृति प्रदान करें। इससे सिंचाई के साथ-साथ पीने के पानी की समस्या तथा मवेशियों के लिए पानी की समस्या का निराकरण हो सकेगा।

Concern over rise in Type 1 Diabetes among children

डा. अशोक बाजपेयी (उत्तर प्रदेश): माननीय सभापति जी, मैं आपकी अनुज्ञा से एक बड़ा गंभीर प्रश्न सदन के संज्ञान में उपस्थित करना चाहता हूँ।

मान्यवर, आज देश में बड़ी संख्या में डायबिटीज-वन के केस बढ़ते जा रहे हैं। डायबिटीज दो तरह की होती है - एक टाइप वन और दूसरी टाइप टू। टाइप वन डायबिटीज के केसेज़ दो साल से चार साल के बच्चों में पाए जाते हैं। आज यह समस्या धीरे-धीरे विकराल रूप लेती जा रही है, क्योंकि ग्रामीण क्षेत्रों में न तो इसकी जाँच और परीक्षण का कोई केन्द्र है और न ही वहाँ के लोग यह जान पाते हैं कि उनके बच्चे टाइप वन डायबिटीज से ग्रसित हैं। इस प्रकार, धीरे-धीरे उनकी स्थिति खराब होती जाती है और जब उनकी हालत गंभीर हो जाती है, तब कही जाकर वे किसी अस्पताल में टैस्ट कराते हैं और फिर उनको मालूम होता है कि उनके बच्चे टाइप वन डायबिटीज के मरीज हैं।

मान्यवर, टाइप वन डायबिटीज के लिए इलाज केवल इंसुलिन है और इंसुलिन पर ही मरीज को जीवित रखा जा सकता है। इस तरह दो साल, तीन साल, चार साल और पाँच साल के बच्चों को लगातार इंसुलिन पर रखना बहुत मुश्किल है। इंसुलिन की व्यवस्था बड़े शहरों में तो उपलब्ध हो जाती है, लेकिन ग्रामीण क्षेत्र में इंसुलिन का उपलब्ध होना काफी मुश्किल है। इसके अलावा, उसको किसी ठंडी जगह पर, फ्रीजर में रखने में भी कठिनाई होती है, क्योंकि वहाँ पर बिजली नही होती है। वहाँ पर इस तरह के रेफ्रिजरेटर्स नही होते हैं, जिनमें बच्चों के लिए इंसुलिन को सुरक्षित रखा जा सके। इसके अलावा, यह गरीब माँ-बाप के लिए बहुत महँगा भी पड़ता है, इसलिए उनके लिए यह संभव नही है कि वे टाइप वन डायबिटीज से पीड़ित अपने बच्चों के लिए लगातार इंसुलिन की व्यवस्था कर सकें।

मान्यवर, कई बार बच्चे हाइपोग्लाइसीमिया में चले जाते हैं, उनका ब्लड शुगर लेवल नीचे गिर जाता है, उन्हें पता नही लगता, बच्चे मूर्छित हो जाते हैं और उनकी स्थिति गंभीर हो जाती है। कई बार जाँच की कमी के कारण उन बच्चों का शुगर लेवल बहुत बढ़ जाता है। इस प्रकार, यह एक गंभीर स्थिति बनी हुई है। टाइप वन डायबिटीज वंशानुगत भी होती है और अगर वंशानुगत परम्परा नही भी है, तब भी बच्चों में यह स्वत: हो जाती है।

मान्यवर, इसका प्रभाव हमारी एक बड़ी आबादी पर पड़ रहा है। उनके लिए इलाज एक बड़ी कठिनाई है। वहाँ पर उन बच्चों का इलाज, उनका समय-समय पर जाँ-चपरीक्षण और शुगर लेवल की जाँच करना संभव नही हो पाता। टाइप वन डायबिटीज एक तरीके से विकलाँगता है, इसलिए सरकार से मेरा आग्रह होगा कि जो बच्चे जन्म से ही टाइप वन डायबिटीज से ग्रसित होते हैं, उनको विकलाँगता की श्रेणी में रखते हुए उनको सारी सुविधाएँ दी जाएँ। इन बच्चों में टाइप वन डायबिटीज के इलाज के लिए सरकार कोई विशेष व्यवस्था करे। उनके लिए सस्ती दरों पर इंसुलिन उपलब्ध कराया जाए, उनके लिए टैस्टिंग किट उपलब्ध कराई जाए, ताकि गाँवों में बच्चों का शुगर लेवल टैस्ट किया जा सके और वे बच्चे, जो टाइप वन डायबिटीज से ग्रसित हैं, उनका समय पर इलाज हो सके।

मान्यवर, इस गंभीर समस्या की ओर मैं आपका और सदन का ध्यान आकर्षित करते हुए

सरकार से माँग करता हूँ कि प्राथमिकता के आधार पर टाइप वन डायबिटीज से लड़ने के लिए समुचित व्यवस्था की जाए। बहुत-बहुत धन्यवाद।

श्री सभापति: यह विषय महत्वपूर्ण है। आपने सुझाव दिया, अच्छा है। मगर, इसमें से एक विषय यह कि उनको विकलाँगता की श्रेणी में रखा जाए, यह अच्छा नही है, क्योंकि इससे बचपन से ही उनका माइंड अपसेट हो जाएगा।

श्री गोपाल नारायण सिंह (बिहार): महोदय, मैं स्वयं को इस विषय के साथ संबद्ध करता हूँ।

श्री सकलदीप राजभर (उत्तर प्रदेश): महोदय, मैं भी स्वयं को इस विषय के साथ संबद्ध करता हूँ।

श्री कैलाश सोनी (मध्य प्रदेश): महोदय, मैं भी स्वयं को इस विषय के साथ संबद्ध करता हूँ।

श्री रामकुमार वर्मा (राजस्थान): महोदय, मैं भी स्वयं को इस विषय के साथ संबद्ध करता हूँ।

डा. सत्यनारायण जटिया (मध्य प्रदेश): महोदय, मैं भी स्वयं को इस विषय के साथ संबद्ध करता हूँ।

डा. विकास महात्मे (महाराष्ट्र): महोदय, मैं भी स्वयं को इस विषय के साथ संबद्ध करता हूँ।

श्री सुरेन्द्र सिंह नागर (उत्तर प्रदेश): महोदय, मैं भी स्वयं को इस विषय के साथ संबद्ध करता हूँ।

श्री राम नाथ ठाकुर (बिहार): महोदय, मैं भी स्वयं को इस विषय के साथ संबद्ध करता हूँ।

श्री राम विचार नेताम (छत्तीसगढ़): महोदय, मैं भी स्वयं को इस विषय के साथ संबद्ध करता हूँ।

श्री रवि प्रकाश वर्मा (उत्तर प्रदेश): महोदय, मैं भी स्वयं को इस विषय के साथ संबद्ध करता हूँ।

श्री जावेद अली खान (उत्तर प्रदेश): महोदय, मैं भी स्वयं को इस विषय के साथ संबद्ध करता हूँ।

† **جناب جاوید علی خان (اترپردیش):** مہودے، میں بھی خود کو اس موضوع کے ساتھ سمبدّ کرتا ہوں۔

श्री विशम्भर प्रसाद निषाद (उत्तर प्रदेश): महोदय, मैं भी स्वयं को इस विषय के साथ संबद्ध करता हूँ।

†Transliteration in Urdu script.

श्री समीर उरांव (झारखंड): महोदय, मैं भी स्वयं को इस विषय के साथ संबद्ध करता हूँ।

PROF. MANOJ KUMAR JHA (Bihar): Sir, I also associate myself with the mention made by the hon. Member.

SHRI ABIR RANJAN BISWAS (West Bengal): Sir, I also associate myself with the mention made by the hon. Member.

SHRI K.J. ALPHONS (Rajasthan): Sir, I also associate myself with the mention made by the hon. Member.

DR. SONAL MANSINGH (Nominated): Sir, I also associate myself with the mention made by the hon. Member.

DR. AMAR PATNAIK (Odisha): Sir, I also associate myself with the mention made by the hon. Member.

DR. SASMIT PATRA (Odisha): Sir, I also associate myself with the mention made by the hon. Member.

Need to frame a comprehensive scheme to protect the interest of workers in various sectors

SHRI M. SHANMUGAM (Tamil Nadu): I would like to draw the attention of the Minister through you, Sir, to the crisis of jobless employees. Due to instability in the current economic scenario, lakhs and lakhs of workers from IT sector, automobile sector, MSME sector and agriculture sector have become jobless. Without any prior notice, they are being shunted out. The leading automobile manufacturer in Tamil Nadu, Ashok Leyland, declared layoff of four days in a week. The TVS, which is known for its product worldwide, declared layoff which it never had in its history since its inception. In Coimbatore, many leading companies like Lakshmi Machine Works, etc., have kept their workers away from job for three days in a week.

The companies which are in the manufacturing process of accessories also could not escape from this tsunami. It is a shocking news that in the Ashok Leyland unit itself, 14,000 contract labourers had been shown the door and they are on the street. They are kept in the dark and don't have any clue about their future. The IT sector is responsible for making 30 per of the workers jobless. The regular employees of these private firms who are kept on layoff are forced to lose half of their monthly salary and